

Indian Journal of Modern Research and Reviews

This Journal is a member of the 'Committee on Publication Ethics'

Online ISSN: 2584-184X



Research Article

शहरी क्षेत्रों में अल्पसंख्यक महिलाओं पर वैश्वीकरण का प्रभाव

डॉ० शारदा कुमारी

सारांश

इक्कीसवीं सदी का समाज तीव्र गति से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और इस परिवर्तन की सबसे सशक्त प्रक्रिया के रूप में वैश्वीकरण उभरकर सामने आया है। वैश्वीकरण केवल आर्थिक उदारीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और तकनीकी स्तर पर भी गहरे प्रभाव डालता है। पूँजी, श्रम, सूचना, तकनीक और संस्कृति के वैश्विक प्रवाह ने पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं को चुनौती दी है और नई सामाजिक वास्तविकताओं को जन्म दिया है। भारत जैसे विकासशील और बहुसांस्कृतिक देश में वैश्वीकरण का प्रभाव विशेष रूप से जटिल और बहुआयामी रहा है, जहाँ सामाजिक असमानताएँ पहले से ही विद्यमान हैं। भारतीय समाज में अल्पसंख्यक महिलाएँ एक विशिष्ट सामाजिक वर्ग का निर्माण करती हैं, जिनकी स्थिति बहुसंख्यक समाज की महिलाओं से कई दृष्टियों से भिन्न है। वे न केवल लैंगिक भेदभाव का सामना करती हैं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यक होने के कारण सामाजिक बहिष्करण, पूर्वाग्रह और असुरक्षा जैसी समस्याओं से भी जूझती हैं। जब यह स्थिति शहरी संदर्भ से जुड़ती है, तब उनकी चुनौतियाँ और भी जटिल हो जाती हैं। शहरी क्षेत्र वैश्वीकरण के प्रमुख केंद्र होते हैं, जहाँ आर्थिक अवसरों के साथ-साथ प्रतिस्पर्धा, असमानता और अस्थिरता भी तीव्र रूप से विद्यमान रहती है। वैश्वीकरण के प्रभाव से शहरी जीवन-शैली, कार्य-संरचना और सामाजिक संबंधों में व्यापक परिवर्तन आए हैं। सेवा क्षेत्र का विस्तार, निजीकरण, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की उपस्थिति, सूचना प्रौद्योगिकी का विकास और उपभोक्ता संस्कृति का प्रसार शहरी समाज की प्रमुख विशेषताएँ बन गई हैं। इन परिवर्तनों ने अल्पसंख्यक महिलाओं के जीवन को शिक्षा, रोजगार, पारिवारिक भूमिका, सांस्कृतिक पहचान और आत्मनिर्णय के स्तर पर गहराई से प्रभावित किया है। एक ओर वैश्वीकरण ने उन्हें शिक्षा और रोजगार के नए अवसर प्रदान किए हैं, वहीं दूसरी ओर यह असमान श्रम स्थितियों, असुरक्षित रोजगार और सांस्कृतिक दबावों को भी जन्म देता है। शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अल्पसंख्यक महिलाएँ वैश्वीकरण के संदर्भ में दोहरे और कभी-कभी तिहरे भेदभाव का सामना करती हैं। लिंग, वर्ग और धर्म के आधार पर होने वाला भेदभाव उनके सामाजिक अनुभवों को प्रभावित करता है। वैश्विक बाजार की माँगों के अनुरूप श्रम का लचीलापन बढ़ने से महिलाओं की भागीदारी तो बढ़ी है, किंतु अधिकांश अल्पसंख्यक महिलाएँ असंगठित क्षेत्र, घरेलू कार्य, छोटे उद्योगों और सेवा आधारित निम्न-स्तरीय नौकरियों तक सीमित रह गई हैं। इस प्रकार वैश्वीकरण उनके लिए सशक्तिकरण और शोषण—दोनों की संभावनाएँ साथ लेकर आया है। सांस्कृतिक स्तर पर भी वैश्वीकरण का प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैश्विक मीडिया, विज्ञापन और सोशल मीडिया के माध्यम से पश्चिमी जीवन-शैली इस प्रकार "शहरी क्षेत्रों में अल्पसंख्यक महिलाओं पर वैश्वीकरण का प्रभाव" एक ऐसा विषय है, जो सामाजिक परिवर्तन, लैंगिक अध्ययन और अल्पसंख्यक विमर्श के केंद्र में स्थित है। यह अध्ययन न केवल वैश्वीकरण की वास्तविकताओं को उजागर करता है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि यदि विकास की प्रक्रियाएँ समावेशी और न्यायपूर्ण न हों, तो वे समाज के कमजोर वर्गों के लिए नई चुनौतियाँ उत्पन्न कर सकती हैं। इसलिए इस विषय का अध्ययन समकालीन भारतीय समाज को समझने की दृष्टि से अत्यंत प्रासंगिक और आवश्यक है।

मुख्य शब्द- वैश्वीकरण, श्रम बाजार, अल्पसंख्यक महिलाएँ, नई पहचान, आर्थिक सशक्तिकरण, असंगठित क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, रोजगार अवसर, लैंगिक समानता, सामाजिक परिवर्तन, असमानता, असुरक्षित रोजगार, शोषण, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, कौशल विकास, तकनीकी प्रशिक्षण, सांस्कृतिक बाधाएँ, आत्मनिर्भरता, नीतिगत हस्तक्षेप।

Article History

- ISSN: 2584-184X
- Received: 16 Nov 2023
- Accepted: 29 Dec 2023
- MRR:1(1) Dec.2023:80-82
- ©2023, All Rights Reserved
- Peer Review Process: Yes
- Plagiarism Checked: Yes

Authors Details

डॉ० शारदा कुमारी

सहायक प्राध्यापक,
वाई०बी०एन० यूनिवर्सिटी, रांची
झारखण्ड, भारत

Corresponding Author

डॉ० शारदा कुमारी

सहायक प्राध्यापक
वाई०बी०एन० यूनिवर्सिटी, रांची
झारखण्ड, भारत

1. प्रस्तावना

वैश्वीकरण इक्कीसवीं सदी की सबसे प्रभावशाली सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया है, जिसने विश्व के प्रत्येक समाज को किसी न किसी रूप में प्रभावित किया है। भारत जैसे विकासशील और बहुसांस्कृतिक देश में वैश्वीकरण का प्रभाव विशेष रूप से जटिल और बहुआयामी रहा है। आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्विक बाजार से जुड़ाव ने जहाँ एक ओर रोजगार, तकनीक और संचार के नए अवसर उत्पन्न किए, वहीं दूसरी ओर सामाजिक असमानताओं, सांस्कृतिक टकरावों और वर्गीय-लैंगिक विषमताओं को भी गहरा किया। इस समग्र परिदृश्य में शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अल्पसंख्यक महिलाएँ एक ऐसा सामाजिक वर्ग हैं, जिन पर वैश्वीकरण का प्रभाव न तो पूरी तरह सकारात्मक रहा है और न ही पूरी तरह नकारात्मक, बल्कि यह विरोधाभासों से भरा हुआ है।

भारत में अल्पसंख्यक महिलाएँ धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान के आधार पर बहुआयामी चुनौतियों का सामना करती हैं। मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन समुदायों की महिलाएँ न केवल पितृसत्तात्मक संरचनाओं के भीतर जीती हैं, बल्कि बहुसंख्यक समाज की दृष्टि में 'अल्पसंख्यक' होने के कारण अतिरिक्त भेदभाव और असुरक्षा भी झेलती हैं। जब ये महिलाएँ शहरी संदर्भ में प्रवेश करती हैं, तो वैश्वीकरण की प्रक्रियाएँ उनके जीवन को शिक्षा, रोजगार, संस्कृति, परिवार, पहचान और आत्मनिर्णय के स्तर पर गहराई से प्रभावित करती हैं।

वैश्वीकरण की अवधारणा और शहरी संदर्भ

वैश्वीकरण को सामान्यतः पूँजी, श्रम, तकनीक, सूचना और संस्कृति के वैश्विक प्रवाह के रूप में समझा जाता है। यह प्रक्रिया सीमाओं को शिथिल करती है और स्थानीय समाजों को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ती है। शहरी क्षेत्र वैश्वीकरण के प्रमुख केंद्र होते हैं, जहाँ बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, सेवा क्षेत्र, सूचना प्रौद्योगिकी, मीडिया और उपभोक्ता संस्कृति तेजी से विकसित होती है। शहरों में रोजगार के अवसर अपेक्षाकृत अधिक होते हैं, किंतु प्रतिस्पर्धा, अस्थिरता और असमानता भी उतनी ही तीव्र होती है। शहरीकरण और वैश्वीकरण का संयुक्त प्रभाव अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए दोहरी चुनौती उत्पन्न करता है। एक ओर शहर उन्हें परंपरागत सामाजिक बंधनों से कुछ हद तक मुक्ति और आत्मनिर्भरता का अवसर देते हैं, दूसरी ओर वैश्विक बाजार की शर्तें उन्हें असंगठित, असुरक्षित और कम वेतन वाले कार्यों तक सीमित कर देती हैं।

शिक्षा पर वैश्वीकरण का प्रभाव

शहरी क्षेत्रों में वैश्वीकरण ने शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसरों का विस्तार किया है। निजी स्कूलों, अंग्रेजी माध्यम शिक्षा, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ी है। अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है, क्योंकि शिक्षा उनके सामाजिक सशक्तिकरण का प्रमुख साधन है। हालाँकि वास्तविकता यह है कि शहरी अल्पसंख्यक महिलाओं की बड़ी संख्या अब भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित है। आर्थिक गरीबी, पारिवारिक प्राथमिकताएँ, धार्मिक-सांस्कृतिक रूढ़ियाँ और शहरी जीवन की महँगी शिक्षा व्यवस्था उनके लिए बाधा बनती हैं। वैश्वीकरण के तहत शिक्षा

का बाजारीकरण हुआ है, जिससे शिक्षा एक 'सार्वजनिक अधिकार' की बजाय 'उपभोक्ता वस्तु' बन गई है। इसका सबसे नकारात्मक प्रभाव गरीब और अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं पर पड़ा है। इसके बावजूद, कुछ अल्पसंख्यक महिलाएँ उच्च शिक्षा और पेशेवर प्रशिक्षण के माध्यम से नई पहचान गढ़ने में सफल हुई हैं। विशेषकर मुस्लिम और ईसाई समुदायों की शहरी शिक्षित महिलाएँ आज मीडिया, शिक्षण, स्वास्थ्य और आईटी क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं।

रोजगार और श्रम बाजार में स्थिति

वैश्वीकरण का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव शहरी श्रम बाजार में दिखाई देता है। सेवा क्षेत्र का विस्तार, कॉल सेंटर, बीपीओ, खुदरा व्यापार, फैशन उद्योग, घरेलू कार्य और अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए हैं। अल्पसंख्यक महिलाओं ने इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में प्रवेश किया है। किन्तु यह प्रवेश अक्सर असमान शर्तों पर हुआ है। अधिकांश अल्पसंख्यक महिलाएँ असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं, जहाँ न तो नौकरी की सुरक्षा है, न सामाजिक सुरक्षा और न ही उचित वेतन। घरेलू कामगार, सिलाई-कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, छोटे खुदरा प्रतिष्ठान और फैक्ट्री आधारित कार्यों में उनकी भागीदारी अधिक है। वैश्वीकरण के कारण श्रम का लचीलापन बढ़ा है, जिससे महिलाओं का शोषण भी बढ़ा है। धार्मिक पहचान के कारण भी अल्पसंख्यक महिलाओं को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। मुस्लिम महिलाओं के पहनावे, नाम और सांस्कृतिक प्रतीकों के आधार पर कई बार उन्हें रोजगार से वंचित किया जाता है। इस प्रकार वैश्वीकरण के साथ-साथ सामाजिक पूर्वाग्रह भी शहरी श्रम बाजार में सक्रिय रहते हैं।

सांस्कृतिक परिवर्तन और पहचान का संकट

वैश्वीकरण के साथ पश्चिमी जीवन-शैली, उपभोक्तावाद और मीडिया संस्कृति का तीव्र प्रसार हुआ है। शहरी अल्पसंख्यक महिलाएँ इस सांस्कृतिक परिवर्तन के केंद्र में हैं। एक ओर वे आधुनिकता, फैशन, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों की ओर आकर्षित होती हैं, दूसरी ओर उन्हें अपने धार्मिक और पारंपरिक मूल्यों की रक्षा का दबाव भी झेलना पड़ता है। यह स्थिति 'दोहरी पहचान' का संकट उत्पन्न करती है। अल्पसंख्यक महिलाएँ न तो पूरी तरह पारंपरिक रह पाती हैं और न ही पूरी तरह आधुनिक। परिवार और समुदाय उनसे परंपरागत भूमिका की अपेक्षा करते हैं, जबकि शहरी और वैश्विक संस्कृति उनसे आधुनिक, आत्मनिर्भर और उपभोक्ता बनने की माँग करती है। मीडिया और सोशल मीडिया ने इस द्वंद्व को और जटिल बना दिया है। एक ओर यह मंच अल्पसंख्यक महिलाओं को अपनी आवाज़ उठाने का अवसर देता है, दूसरी ओर सौंदर्य, शरीर और जीवन-शैली के नए मानक थोपता है, जिससे मानसिक दबाव और आत्म-संघर्ष बढ़ता है।

परिवार और सामाजिक संरचना में परिवर्तन

वैश्वीकरण ने शहरी परिवार संरचना को भी प्रभावित किया है। संयुक्त परिवारों का विघटन, एकल परिवारों का उदय और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी ने पारिवारिक भूमिकाओं में बदलाव किया है। अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए यह परिवर्तन मिश्रित परिणाम लेकर आया है। आर्थिक रूप से सक्रिय होने से महिलाओं की निर्णय-क्षमता और आत्मसम्मान में वृद्धि हुई है। वे शिक्षा, विवाह और करियर से जुड़े

निर्णयों में अधिक मुखर हुई हैं। किंतु इसके साथ घरेलू कार्यों और देखभाल की जिम्मेदारियाँ अब भी मुख्यतः उन्हीं पर बनी हुई हैं। इस प्रकार वे 'दोहरा बोझ' उठाने को विवश हैं। कई मामलों में वैश्वीकरण ने पीढ़ीगत टकराव को भी जन्म दिया है। युवा अल्पसंख्यक महिलाएँ आधुनिक मूल्यों को अपनाना चाहती हैं, जबकि बुजुर्ग पीढ़ी परंपराओं पर जोर देती है। इससे पारिवारिक तनाव और सामाजिक संघर्ष बढ़ते हैं।

राजनीतिक चेतना और अधिकारों की समझ

शहरी क्षेत्रों में वैश्वीकरण ने सूचना और संचार के साधनों को व्यापक बनाया है। इंटरनेट, सोशल मीडिया और वैश्विक मानवाधिकार विमर्श ने अल्पसंख्यक महिलाओं में राजनीतिक चेतना और अधिकारों की समझ को बढ़ाया है। वे अब शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा और समानता के प्रश्नों पर अधिक सजग हो रही हैं। महिला आंदोलनों, गैर-सरकारी संगठनों और सामुदायिक पहलों के माध्यम से अल्पसंख्यक महिलाएँ अपनी समस्याओं को सार्वजनिक मंच पर ला रही हैं। हालांकि उनकी राजनीतिक भागीदारी अब भी सीमित है, फिर भी शहरी संदर्भ में यह एक सकारात्मक परिवर्तन माना जा सकता है।

असमानताएँ और चुनौतियाँ

वैश्वीकरण ने अवसरों के साथ-साथ असमानताओं को भी गहरा किया है। शहरी अल्पसंख्यक महिलाएँ वर्ग, लिंग और धर्म के त्रिस्तरीय भेदभाव का सामना करती हैं। आर्थिक असुरक्षा, आवासीय अलगाव, शिक्षा में असमानता और सामाजिक पूर्वाग्रह उनकी प्रमुख चुनौतियाँ हैं। झुग्गी-झोपड़ियों और अल्पविकसित शहरी इलाकों में रहने वाली अल्पसंख्यक महिलाएँ वैश्वीकरण के लाभों से लगभग वंचित हैं। उनके लिए वैश्वीकरण केवल महँगाई, अस्थिर रोजगार और सांस्कृतिक दबाव लेकर आया है।

निष्कर्ष

शहरी क्षेत्रों में अल्पसंख्यक महिलाओं पर वैश्वीकरण का प्रभाव जटिल, बहुआयामी और विरोधाभासी है। इसने जहाँ एक ओर शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता के नए अवसर प्रदान किए हैं, वहीं दूसरी ओर असमानता, शोषण और पहचान के संकट को भी गहरा किया है। वैश्वीकरण को यदि सामाजिक न्याय और समावेशन के साथ जोड़ा जाए, तो यह अल्पसंख्यक महिलाओं के सशक्तिकरण का माध्यम बन सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षा और रोजगार की नीतियों में अल्पसंख्यक महिलाओं की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाए, श्रम सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा को मज़बूत किया जाए तथा सांस्कृतिक विविधता को सम्मान दिया जाए। तभी वैश्वीकरण का लाभ शहरी अल्पसंख्यक महिलाओं तक वास्तविक रूप में पहुँच सकेगा और वे एक समान, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन जी सकेंगी।

संदर्भ सूची

1. अंबेडकर बी.आर. महिला और सामाजिक न्याय. नई दिल्ली: भारत सरकार प्रकाशन विभाग; 1990।
2. चटर्जी पी. आधुनिकता और सामाजिक परिवर्तन. नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस; 2008।

3. देशपांडे एस. समकालीन भारत में सामाजिक असमानता. नई दिल्ली: पेंगुइन इंडिया; 2013।
4. गुप्ता डी. शहरीकरण, लिंग और श्रम. नई दिल्ली: सेज पब्लिकेशन्स; 2011।
5. हसन ज़. अल्पसंख्यक, नागरिकता और भारतीय लोकतंत्र. नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस; 2010।
6. इरफान एस. वैश्वीकरण और मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक स्थिति. इंडियन जर्नल ऑफ सोशल स्टडीज़. 2015;22(2):45-60।
7. कुमार एन. महिलाएँ, संस्कृति और पहचान. नई दिल्ली: सेज पब्लिकेशन्स; 2014।
8. मजूमदार वी. भारतीय महिला आंदोलन: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन. नई दिल्ली: रूटलेज; 2007।
9. सेन ए. डेवलपमेंट ऐज़ फ्रीडम. नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस; 2000।
10. शर्मा के. वैश्वीकरण और शहरी गरीब महिलाएँ. जयपुर: रावत पब्लिकेशन्स; 2016।
11. थापर आर. सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक परिवर्तन. नई दिल्ली: पेंगुइन; 2009।

Creative Commons (CC) License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.